दैनिक जागरण

शिखर पर पहुंचना आसान परंतु उस पर टिके रहना मुश्किल होता है

खस्ताहाल बैंक

पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में घपलेबाजी के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से यह सूचना देना घोर निराशाजनक है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने उसके साथ 44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। वास्तव में यह भी एक किस्म की धोखाधड़ी ही है कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने अब जाकर यह सार्वजनिक करना जरूरी समझा कि चोकसी ने उसके साथ ठगी की है। क्या यह जानकारी तभी सामने नहीं आनी चाहिए थी जब चोकसी और नीरव मोदी के देश से भाग जाने की खबर आई थी? कर्ज लेकर उसे चुकाने से जानबूझकर इन्कार करने अथवा छल-छद्म से लोन लेकर उसे हड़प करने या फिर विदेश भागने वाले तत्वों के बारे में हमारे बैंक जिस तरह जानकारी देने में शिथिलता बरत रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वे जरूरी सूचनाएं छिपाने में अभी भी माहिर हैं। क्या अब भी बैंकों का ऑडिट सही तरह नहीं हो रहा है? क्या रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक उसके नियम-निर्देशों का पालन करें? एक सवाल यह भी है कि जब नोटबंदी के समय यह पता चल गया था कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली भरोसेमंद नहीं तो फिर उसी समय उनके नियमन की उपयुक्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यह सवाल इसलिए, क्योंकि पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में घपला होने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के बैंकों के नियमन की खामियों पर रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय के अधिकारी चर्चा करेंगे। क्या इस चर्चा के लिए घोटाला होने का इंतजार किया जा रहा था?

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो सहकारी बैंकों का संचालन बेहतर बनाने के लिए कानून बनाया जाएगा। कायदे से यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। मोदी सरकार को अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की खस्ता हालत का आभास हो गया था। सरकार की ओर से बैंकों की कार्यप्रणाली दुरुस्त करने के लिए कई कदम भी उठाए गए, लेकिन उनकी स्थिति में अभी तक सुधार नहीं आ सका है। इसका प्रमाण सरकारी बैंकों की ओर से करीब पौने तीन लाख करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डालना है। इसका मतलब है कि बैंकों को भारी-भरकम एनपीए से मुक्ति नहीं मिलने वाली। अगर बैंकों के बारे में इसी तरह की सूचनाएं सामने आती रहीं तो उनके साथ-साथ सरकार की साख को भी चोट पहुंचेगी और लोगों का भरोसा भी डिगेगा। बेहतर हो कि सरकार बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमर कसे, क्योंकि उनकी हालत ठीक होने का नाम नहीं ले रही।

सुधार की दरकार

उत्तराखंड का खर्च हर साल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से आमदनी के बढ़ने की रफ्तार धीमी है। आमदनी और खर्च के बीच यह खाई प्रदेश सरकार के माथे पर भी बल डाले हुए है। एक ओर राजस्व बढ़ाने के नए तरीकों को आजमाने से बचा जा रहा है तो दूसरी ओर राजस्व की परंपरागत मदों में वृद्धि नहीं दिखना चिंता का कारण है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में आबकारी, खनन और ऊर्जा से आमदनी बढ़ने के बजाय घट गई। यह झटका खनन में ज्यादा है। बीते वर्ष की तुलना में 17 फीसद की कमी आई, जबकि आबकारी में सात फीसद की गिरावट रही है। विद्युत कर की वसूली के मामले में संबंधित महकमे ने तेजी से गोता लगा दिया। विद्युत कर राजस्व 64 फीसद घटा है। खनन में आमदनी को लेकर ज्यादा उम्मीदें संजोई तो गईं, लेकिन इन पर खरा नहीं उतरा जा सका। यह हालत तब है, जब अवैध रूप से खनन बढ़ने को लेकर सरकार के स्तर पर भी लगातार चिंता जताई जा रही है। राजस्व आमदनी को लेकर संबंधित महकमों के नजरिये और कार्यप्रणाली दोनों में ही सुधार नजर नहीं आ रहा है। राजस्व के नए क्षेत्रों को चिन्हित करने, कर चोरी रोकने और कर वसूली में तेजी लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर महकमों की सुस्ती बरकरार है। ऊर्जा विभाग को बिजली चोरी रोकने में न तो कामयाबी मिल रही है, न ही वसूली में अपेक्षित इजाफा हुआ है। सरकार के तमाम दबाव और ऊर्जा निगम के इसे मुहिम के तौर पर प्रचारित करने के बावजूद हालात सुधरते नहीं दिखते। सरकार पूरी वित्तीय प्रणाली को ऑनलाइन करने की कवायद में जुटी है। महकमों का इस कवायद से तालमेल नहीं बैठाने का नतीजा दोतरफा नुकसान के रूप में सामने है। राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है तो बजट के उपयोग को लेकर भी महकमे ढुलमुल रवैया छोड़ नहीं सके हैं। हालांकि शासन स्तर से महकमों को बजट राशि जारी करने में तेजी आई है। इसे ऑनलाइन व्यवस्था का ही नतीजा माना जा रहा है, लेकिन बजट खर्च के मामले में महकमों की धीमी गति कई सवाल खड़े करती है। बजट खर्च की कार्ययोजना खुद तैयार करने वाले महकमों का बजट खर्च में फिसड्डी रहना कार्ययोजना को लेकर उनकी तैयारी पर अंगुली उठाने को काफी है। इसका खामियाजा वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने मार्च में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने की परंपरा के रूप में सामने है। इस परंपरा को तोड़ने के लिए सरकार को नीतिगत और व्यावहारिक दोनों स्तर पर फैसले लेने होंगे।

भारत-चीन दोस्ती का नया दौर

संजय गुप्त

आज जब 21 वीं सदी एशिया की सदी मानी जा रही है तब उचित यही है कि भारत-चीन मिलकर काम करें

अवधेश राजपूत

तमिलनाडु के मामल्लपुरम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच अनौपचारिक वार्ता के दूसरे दौर ने यही बताया कि दोनों देश फिलहाल मतभेद वाले मसले छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मौजूदा स्थितियों में यही उचित है, लेकिन ऐसे मसलों को सुलझाए बगैर भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहना संभव नहीं। सच तो यह है कि इन मसलों को सुलझाकर ही आपसी भरोसे की कमी को दूर किया जा सकता है। वुहान के बाद मामल्लपुरम में हुई अनौपचारिक बैठक की खास बात यह रही कि उसमें कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा। इसका महत्व इसलिए है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के भारत के फैसले पर चीन ने न केवल एतराज जताया था, बल्कि इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ले गया। यही नहीं बीते दिनों जब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान सेना प्रमुख बाजवा के साथ बीजिंग पहुंचे तो चीन ने कश्मीर पर नजर रखने की बात कहते हुए उसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुरूप करने की बात कही। इसके एक दिन पहले ही उसने कहा था कि भारत-पाक को कश्मीर का समाधान मिलकर करना चाहिए। इस माहौल में इसका अंदेशा था कि चीन मामल्लपुरम में कश्मीर राग छेड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि चीन जानता था कि भारत क्या चाहता है? उसे यह भी आभास होगा कि कश्मीर मसला उठाने के क्या नतीजे हो सकते हैं?

मामल्लपुरम में दोनों देशों के नेताओं के बीच विभिन्न मसलों पर करीब छह घंटे बात हुई। दरअसल अनौपचारिक वार्ता में नेता किसी भी विषय पर बात करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं होता जिसके हिसाब से बात करना आवश्यक हो। दोनों देशों के बीच वुहान में जब अनौपचारिक वार्ता हुई थी उस समय भारत-चीन डोकलाम विवाद से उबरे ही थे। तब कयास लगाए गए थे कि वुहान में डोकलाम की छाया गहरी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों नेताओं ने आपसी मसलों पर खुलकर वार्ता की। मामल्लपुरम में भी ऐसा ही हुआ। यहां दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत संबंधों को नई ऊंचाई देने की कोशिश की और साथ ही आतंकवाद, कट्टरता, व्यापार, निवेश आदि मसलों पर बात की। इसके अलावा दोनों देशों के लोगों में संपर्क-संवाद बढ़ाने की जरूरत जताई। इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत में चीन के रुख को लेकर आशंका बनी रहती है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। 1962 में उसके साथ हुए युद्ध की कड़वी यादें अभी भुलाई नहीं जा सकी हैं। इसकी वजह यह भी है कि चीन अपने विस्तारवादी रवैये का प्रदर्शन करता रहता है। वह आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद खुद को एक सैन्य महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने में जुटा है। वह भारत की घेरेबंदी करने के साथ पाकिस्तान को भारतीय हितों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहा है।

मामल्लपुरम में बातचीत संतोषजनक रहने के बाद भी यह कहना कठिन है कि चीन पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना छोड़ेगा। चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आर्थिक गलियारा बना रहा है वह भारत की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। चीन अरब सागर तक अपनी पहुंच आसान बनाने के लिए इस गलियारे का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी कर रहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। चीन यह जानते हुए भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहने को तैयार है कि वह भारत में आतंक फैलाने में लगा हुआ है। चीन कश्मीर पर पाकिस्तानपरस्ती दिखाने के साथ जब-तब अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहता है। इसी तरह का दावा वह लद्दाख पर भी करता है, लेकिन वह अक्साई चिन पर भारत के दावे को और साथ ही मकमहोन सीमा रेखा को महत्व देने को तैयार नहीं। वह सीमा विवाद सुलझाने का भी इच्छुक नहीं दिखता। यह अच्छी बात है कि सीमा विवाद के बाद भी बीते 40 वर्षों से सीमा पर कोई गोली नहीं चली। मामल्लपुरम में दोनों देशों के बीच सीमा पर होने वाले तनाव को टालने पर सहमति बनी, लेकिन बात तब बनेगी जब इसके अनुकूल नतीजे भी सामने आएंगे।

चीन के साथ कारोबारी रिश्तों पर बात होनी आवश्यक थी, क्योंकि आपसी व्यापार का पलड़ा चीन के पक्ष में अधिक झुका है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 55 अरब डॉलर है। मामल्लपुरम में दोनों देश व्यापार और निवेश पर चर्चा के लिए एक नए तंत्र की स्थापना करने और उन सेक्टरों की पहचान करने को तैयार हुए जहां निवेश किया जा सकता है। चीन ने भारतीय कारोबारियों को निवेश का निमंत्रण भी दिया। दरअसल अमेरिका से तनातनी के चलते अमेरिकी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेटने के लिए तैयार हैं। यह चीन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उसकी विकास दर भी घट रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी अर्थव्यवस्था अगले कुछ सालों में डगमगा सकती है। ऐसे में चीन का भारत की ओर देखना स्वाभाविक है। चीन को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ कारोबारी और सामाजिक-सांस्कृतिकरिश्तों को नई दिशा देना उसके अपने हित में है। भारत और चीन न केवल क्षेत्र और आबादी के लिहाज से बड़े देश हैं, बल्कि दोनों व्यापक विविधता और प्राचीन संस्कृति वाले देश भी हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि पिछले दो हजार साल में अधिकांश समय भारत-चीन आर्थिक महाशक्ति रहे हैं और वर्तमान सदी में भी दोनों देश इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।

मामल्लपुरम में आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर बात होना पाकिस्तान के लिए नसीहत है, लेकिन आखिर चीन इसकी अनदेखी कैसे कर सकता है कि वहां की राजनीति तो आतंकवाद और कट्टरपंथ की धुरी पर ही घूमती है। चीन अपने यहां के उइगर मुसलमानों पर इसी बहाने सख्ती कर रहा है कि वे आतंकवाद के रास्ते पर न जाने पाएं। कश्मीर पर नजर रखने की बात करने वाले चीन को यह पता होना चाहिए कि हांगकांग और तिब्बत के मसले उसकी कमजोर कड़ी हैं। उसे कश्मीर पर कुछ कहने से पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। इसके साथ ही उसे यह भी पता होना चाहिए कि भारत वैसा देश नहीं जिसे निर्देशित किया जा सके। वास्तव में यह चीन की जिम्मेदारी है कि वह भारत की चिंताओं को समझे। इससे ही दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। देखना है कि चीन भारत की चिंताओं का समाधान करने के लिए आगे आता है या नहीं? चीन को इस पर आत्मचिंतन करना होगा कि आखिर वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय हितों के खिलाफ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों करता रहा और इससे उसे बदनामी के सिवाय और क्या मिला? आज जब 21वीं सदी एशिया की सदी मानी जा रही है तब उचित यही है कि भारत-चीन मिलकर काम करें। ऐसा करके वे अपने हितों की रक्षा करने के साथ ही विश्व को भी दिशा दिखा सकते हैं।

response@jagran.com

आपदाओं का असर घटाने की पहल

पीके मिश्रा

ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता बढ़ रही है जो आपदाओं को सहन करने में समर्थ हो सके

दुनिया में हर साल 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी आइडीडीआर मनाया जाता है। इस दिन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समुदायों और सरकारों के प्रयासों को याद किया जाता है। 2015 में आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद, 'सेंदाई सेवन' अभियान के तहत इस मुहिम की शुरुआत हुई। यह सात लक्ष्यों पर केंद्रित है। इस वर्ष का विषय 'जोखिम वाली अवसंरचनाओं यानी आधारभूत ढांचे को आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने और बुनियादी सेवाओं में बाधा' से जुड़े लक्ष्य पर केंद्रित है। इस साल अभी तक मोजांबिक, बहामास और भारत (ओडिशा चक्रवात) प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए हैं। इनसे हुए नुकसान ने ऐसी अवसंरचना के निर्माण की जरूरत को रेखांकित किया जो आपदाओं को सहन करने में समर्थ हो सके। ओडिशा में आए चक्रवात में ही अकेले बिजली क्षेत्र को लगभग 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इससे यही सबक मिला कि आपदा रोधी अवसंरचना में निवेश का लंबे समय तक कैसे फायदा हो सकता है? विश्व बैंक की सहायता वाले चक्रवात जोखिम शमन कार्यक्रम के तहत तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में बिजली वितरण नेटवर्क के भूमिगत केबल बिछाने में निवेश किया गया है। इससे इन क्षेत्रों में आपदा के बाद बिजली की आपूर्ति कुछ दिनों के भीतर ही बहाल की जा सकती है जबकि अभी ऐसे इलाकों में कई हफ्ते लग जाते हैं। इससे बिजली की आपूर्ति में बाधा से रोजी-रोटी पर पड़ने वाले असर को भी कम से कम किया जा सकता है। भारत और दुनिया भर में जन उपयोगी सेवाओं को इस तरह के अनुभवों को करीब से देखने और अपनी अवसंरचना में उन्हें शामिल करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

भविष्य में अवसंरचना क्षेत्र में भारी निवेश होगा। इन अवसंरचनाओं को प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदा और जोखिम भी झेलने होंगे। इनमें कुछ आपदाएं अप्रत्याशित हो सकती हैं। इस दौरान प्राकृतिक जोखिम के रूप भी बदल सकते हैं। ऐसे में अवसंरचना प्रणाली के डिजाइन, निर्माण, परिचालन और रखरखाव को जोखिम झेलने लायक बनाना होगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी होगा, क्योंकि आपदाओं की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र में दो तिहाई नुकसान अवसंरचना से जुड़ा होता है। इसका सबसे अधिक असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ता है और उसे आपदा से उबरने में अच्छा-खासा समय लग जाता है। अवसंरचना प्रणाली का टिकाऊ होना न केवल आपदा प्रबंधन, बल्कि विकास से जुड़ी चिंता का मुद्दा भी है। घरेलू और वैश्विक बाजारों से संपर्क और पहुंच तथा बिजली, पानी और सक्षम संचार प्रणाली आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करते हैं। यह बात सतत विकास लक्ष्य में भी उल्लिखित है।

टिकाऊ अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, मानक, प्रशासन व्यवस्था और क्षमता की जरूरत होती है, लेकिन इसमें जितना निवेश होता है उसकी तुलना में कहीं अधिक लाभ की संभावना होती है। ओडिशा का उदाहरण इसका प्रमाण है। विश्व बैंक के हालिया अध्ययन के अनुसार आपदारोधी प्रक्रिया को मजबूत बनाने में निवेश किए जाने वाले एक अमेरिकी डॉलर से सामाजिक-आर्थिक नुकसान के संदर्भ में चार अमेरिकी डॉलर के बराबर बचत होती है। संभावित वृहद अवसंरचना निवेश, चाहे वह नवीन/हरित विकास के रूप में हो या फिर संशोधित मौजूदा अवसंरचना के रूप में हो, वह आपदारोधी विकास के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। यह दीर्घावधि में आशंकित नुकसान के प्रति हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आपदारोधी अवसंरचना के विकास के लिए तीन मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। पहला, अवसंरचना को इस प्रकार विकसित किया जाए कि वह आबादी के पूरे आर्थिक दायरे के लिए भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करे जिसमें सभी कमजोर वर्ग शामिल हों। दूसरा, अवसंरचना विकास को विभिन्न सेक्टरों के मद्देनजर अधिक एकीकृत दृष्टिकोण रखना चाहिए और तीसरा, आपदारोधी अवसंरचना का विकास विश्व की बेहतरीन कार्यप्रणाली के अनुकूल हो और वह स्थानीय और राष्ट्रीय संदर्भों को पूरा करता हो। कारगर आपदारोधी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस कार्यप्रणाली में राष्ट्र के विकास की दिशा को बदलने की क्षमता होती है और तेज आर्थिक विकास का रास्ता सुनिश्चित होता है।

आपदारोधी अवसंरचना के महत्व को रेखांकित करते हुए आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 सूत्री एजेंडा सभी सेक्टरों के विकास के संबंध में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिद्धांतों की जरूरत पर बल देता है। इसमें आपदारोधी अवसंरचना के लिए वैश्विक गठबंधन भी शामिल है, जिसकी घोषणा 23 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्ययोजना के शिखर सम्मेलन में हुई थी। आपदा जोखिम में कमी के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से भारत के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में आपदारोधी अवसंरचना के वैश्विक गठबंधन में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई। इन देशों में अग्रणी बुनियादी संरचना प्रणाली वाले देश, बुनियादी ढांचे के अभाव वाले देश और विकासशील देश शामिल हैं। ऐसे देश इसकी जरूरत और प्रासंगिकता को मानने लगे हैं। यह गठबंधन सरकारों के साथ मानक स्थापित करने वाले संगठनों, वित्त प्रदाताओं, बीमाकर्ताओं और अकादमिक संस्थानों को एक साथ लाने का काम करेगा।

चूंकि विद्युत, दूरसंचार और परिवहन जैसे विभिन्न बुनियादी संरचना क्षेत्रों के बीच आपसी निर्भरता है इसलिए आपदा रोधी प्रणाली बनाने के लिए इन क्षेत्रों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि आपदा जोखिम प्रबंधन एकमात्र आपदा प्रबंधन प्राधिकार की भूमिका को छोड़कर व्यापक हितधारक श्रृंखला की ओर आगे बढ़े। आपदारोधी अवसंरचना के लिए वैश्विक गठबंधन के संस्थापक के रूप में भारत के पास विभिन्न देशों से सीखने और अनुभव प्रदान करने का अवसर है। उक्त गठबंधन समान सोच वाले अंशभागियों को समान वैश्विक उद्देश्य से निर्देशित मंच पर लाएगा। यह आगे बढ़ने और आपदा एवं जलवायु रोधी विकास के वैश्विक पथ पर चलने का उचित समय है।

(लेखक प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

निश्चित दायरा

प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित दायरा होता है। बहुधा हम इसे मर्यादा से जोड़कर देखते हैं। यह बात हमें समझनी चाहिए, लेकिन हम इसे समझने का प्रयास नहीं करते। उल्टे उस दायरे की इस वास्तविकता को तोड़ने के उपक्रम में लगे रहते हैं। इससे नैतिक मूल्यों के पतन की शुरुआत हो जाती है। धीरे-धीरे यह व्यक्ति की मानसिकता में शामिल हो जाता है। ऐसी मानसिकता के पीछे तीन कारक विद्यमान हैं। ये हैं सपने, लोभ और परस्पर प्रतिस्पर्धा। ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं। हर मनुष्य बेहतरी चाहता है और इसके लिए कदाचित कुछ अनुचित भी कर गुजरता है। ऐसा लोभ की प्रवृत्ति के कारण होता है। बेहतर पाने के सपने और लोभ दोनों समांतर चलते हैं। यहा नाकामी की आशंका रहती है, क्योंकि मनुष्य अपने सपनों को ही लक्ष्य मान बैठता है और इसमें संतुलन, समर्पण, समन्वय और अनुशासन का अभाव पाया जाता हैं। तीसरा कारक परस्पर प्रतिस्पर्धा है जो न चाहते हुए भी मनुष्य को अनेक सीमाएं तोड़ने के लिए उकसाती है। प्रतिस्पर्धा मनुष्य की शुरुआत से ही स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है जिसके कारण मनुष्य ने प्रगति भी की है, परंतु जो तय दायरों को तोड़कर प्रतिस्पर्धा हो, उसमें संतुलन समाप्त हो जाता है।

हम इस दायरे को आदतन तोड़ना चाहते हैं एवं थोड़ा और विस्तार करना चाहते हैं जो कुछ हद तक प्रगति के लिए उचित भी होता है। मगर दायरे को तोड़ने की भी एक सीमा होती है, क्योंकि इसके बाद असंतुलन का स्तर बढ़ता जाता है और असंतुलन बढ़ने से निरंतर चल रही अनेक क्रियाएं अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। हमारा मन किसी दायरे को मानने को जल्दी तैयार ही नहीं होता और हम इसे अपनी कमजोरी मानने लगते हैं जो हमारी गलतफहमी है। हमें यह समझना चाहिए कि 'यह दायरा' हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि मनुष्य जब अपने कार्य के दायरे को पहचान लेता है और उसे सपनों से लक्ष्य में तब्दील कर जिंदगी में कोई कार्य करता है तो वह कार्य व्यवस्थित होने के साथ साथ दृढ़निश्चय, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण रहता है।

शिवांशु राय

जलवायु परिवर्तन की सुलझती गुत्थी

मुकुल व्यास

एक क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी पर लघु हिमयुग शुरू हो गया था जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं

वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 12,800 वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया जिसके बाद जलवायु परिवर्तन हुआ और कई प्रजातियां एकदम विलुप्त हो गईं। यह अनुमान दक्षिण अफ्रीका में मिले एक नए प्रमाण के आधार पर लगाया है। इसके लिए वंडरक्रेटर नामक स्थान की प्राचीन मिट्टी का विश्लेषण किया और वहां प्लेटिनम के उच्च स्तर का पता लगाया। उन्होंने कहा कि इससे 'यंगर ड्रायास इंपेक्ट' अवधारणा को समर्थन मिलता है। इसके अनुसार एक टूटते हुए क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी पर लघु हिमयुग का दौर शुरू हो गया था। क्षुद्रग्रह के टुकड़े उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया में गिरे थे। इन प्रहारों के बाद धूल और रेत की पतली परत ने करीब पांच करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ढक दिया था।

इस परत में प्लेटिनम और सूक्ष्म हीरे शामिल थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगी, जिससे सर्दियों का दौर शुरू हुआ और लंबे समय तक जलवायु में बदलाव आते रहे तथा प्लीस्टोसीन युग के बड़े-बड़े जीव विलुप्त हो गए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिमयुग से मानव आबादियां अस्तव्यस्त हो गईं। इसके अलावा दर्जनों स्तनपायी प्रजातियां लुप्त हो गईं जिनमें मैमथ (हाथियों की एक प्रजाति) और विशाल जीव शामिल हैं। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन मिट्टी के नमूनों में प्लेटिनम के स्तर में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि क्षुद्रग्रह के टुकड़े पृथ्वी से टकराए थे। उल्कापिंडों में प्लेटिनम का अंश काफी अधिक होता है। दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया के निकट लिंपोपो प्रांत में वंडरक्रेटर के अलावा दुनिया में 30 और स्थलों पर प्लेटिनम के स्तर में वृद्धि देखी गई है। ऐसे अधिकांश क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में हैं।

दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग स्थित विटवाटरसरंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की खोज से इस थ्योरी को बल मिलता है कि उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के विश्वव्यापी प्रभाव हुए थे। अभी तक इसके प्रमाण सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही दर्ज थे। विटवाटरसरंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक फ्रांसिस ठाकरे का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में देखी गई प्लेटिनम के लेवल में वृद्धि यह साबित करती है कि दुनिया भर में अनेक बड़े जानवरों की विलुप्ति उल्कापिंड के एक या अनेक प्रहारों की वजह से हुई थी। यंगर ड्रायास के समय उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के अनेक बड़े जानवरों का सफाया हो गया था।

इसी अवधि में दक्षिण अफ्रीका में विशाल जेब्रा और विशालकाय जंगली भैंस सहित बड़े जानवरों की कुछ प्रजातियां लुप्त हो गईं। डॉ. ठाकरे ने कहा कि हमारी खोज 'यंगर ड्रायास इंपेक्ट' अवधारणा का समर्थन करती है। हमें इस विचार पर गहराई से अध्ययन करना चाहिए कि पृथ्वी पर किसी कोने में गिरने वाले क्षुद्रग्रह ने विश्वयापी स्तर पर जलवायु परिवर्तन किया होगा। यह इस बात का संकेत है कि किसी क्षुद्रग्रह या उल्कापिंड प्रहार ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया होगा।

(लेखक विज्ञान विषय के जानकार हैं)

राजरंग

कहां थे हुजूर?

सूचना क्रांति के इस दौर में जब सूचनाओं के आदान-प्रदान में फटाफट सब कुछ देखने और पढ़ने को मिल रहा है, ऐसे में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका तंत्र अब भी सुस्त चाल से आगे बढ़ रहा है। इसका जीता जागता नमूना देखने को मिला गांधी जयंती के अवसर पर। असल में हुआ कुछ यूं कि दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार देश के अलग-अलग अखबारों और पत्रिकाओं के साथ साझा किए जो गांधी जयंती पर प्रकाशित भी हुए, लेकिन इसी होड़ में दो बड़े वामपंथी नेता इतने पीछे रह गए कि उनके लिखे लेख अखबार के दफ्तरों तक गांधी जयंती की शाम को प्रकाशन के लिए पहुंचे। अब ऐसे में लेख तो नहीं छपा, लेकिन मुफ्त में जल्दी सोकर जागने की नसीहत जरूर इस दल के इन नेताओं मिल गई।

उल्टा पड़ा दांव

पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से गोबैकमोदी हैशटैग वाले हजारों ट्वीट के प्रभाव में आकर कई द्रमुक नेता भी बह गए। द्रमुक नेता भी गोबैकमोदी हैशटैग से ट्वीट करने लगे, लेकिन समस्या उस समय उत्पन्न हो गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरागत तमिल वेशभूषा में चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग के साथ नजर आए। तमिलनाडु समेत पूरी दुनिया में फैले तमिल समुदाय ने मोदी के इस पहनावे का जबरदस्त समर्थन किया और द्रमुक नेताओं की गोबैकमोदी हैशटैग वाले ट्वीट पर जबरदस्त खिंचाई शुरू कर दी। फिर क्या था, द्रमुक नेताओं ने आनन-फानन में गोबैकमोदी हैशटैग वाले ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए। इसके बाद द्रमुक नेताओं ने पूरी तरह चुप्पी साध ली। वहीं गोबैकमोदी हैशटैग के पाकिस्तानी कनेक्शन की पोल खुलने के बाद डोंटगोबैकमोदी हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा।

मंत्री जी की शोहरत

वैसे तो मंत्रीजी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन दिनों महकमे की वजह से उनका यह ग्राफ और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। खुद मंत्री जी भी इस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मामला यह है कि मंत्री जी एक ऐसे विभाग का भी जिम्मा संभाल रहे हैं जो मौसम से जुड़ी सटीक जानकारियां दे रहा है। ऐसे में स्थिति यह हो गई है कि उन्हें जानने वाला हर कोई अब अपने किसी बड़े कार्यक्रम या फिर बेटे-बेटी की शादी की तारीख तय करने से पहले उनकी राय लेना बिल्कुल भी नहीं भूलता। वैसे भी यह नुस्खा मंत्री जी का आजमाया हुआ है। खुद के बेटे की शादी में मौसम को लेकर महकमे की ओर से जो जानकारी दी गई थी, वह शत-प्रतिशत सच साबित हुई थी। मंत्री जी ने पिछले दिनों यह किस्सा महकमे के अधिकारियों को सुनाया तो सभी के चेहरे भी खुशी से दमक उठे। अब तो दोस्तों के साथ महकमे के अफसर भी मंत्री जी की तारीफ करने नहीं थकते हैं। कुल मिलाकर यहां मौसम और माहौल दोनों बढ़िया हैं।

अपशकुन के शिकार

आला अफसरों और नेताओं को अपशकुन की बीमारी सबसे ज्यादा पकड़ती है। सरकार गठन के छह महीने से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन कई बड़े अफसरों और नेताओं के दफ्तर की दिशा व दशा में अभी भी सुधार का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे ही एक भारी भरकम विभाग के मंत्री शास्त्री भवन में अपने पूर्व निर्धारित कार्यालय का पुनरोद्धार करा रहे हैं। इसकी जगह उन्हें अपने एक राज्यमंत्री के खाली पड़े ऑफिस में अस्थाई तौर पर बैठा दिया गया। वहां बैठे उन्हें दो-तीन दिन ही हुए थे कि चमचों ने उन्हें इस दफ्तर के अपशकुन की कहानी सुना दी। फिर क्या था? अगले ही दिन मंत्री जी भाग खड़े हुए। अब उन्हें और कहीं बैठाने के लिए अफसरों की सांसें अटक गईं। एक बार फिर चमचे आगे आए और वहीं पास के कांफ्रेंस रूम में बड़े साहब का दफ्तर जमा दिए। उनके असल दफ्तर की दशा और दिशा को लेकर कई जगह के पंडित पत्रा बांच रहे हैं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाश